



## International Journal of Research in Academic World



Received: 19/October/2023

IJRAW: 2023; 2(11):41-44

Accepted: 27/November/2023

### कोविड के बाद रोजगार की चुनौतियां

\*डॉ. विश्वनाथ पांडे

\*<sup>1</sup>असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत।

#### सारांश

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के निस्संदेह कामकाजी आबादी के एक बड़े वर्ग को तनाह कर दिया है। देश में लाखों कामगार रोग की आशंका और रोजगार छूट जाने की वजह से अपन पैतृक स्थानों की ओर लौट गये। महामारी के कारण नौकरी खोना गंभीर वास्तविकता है। वर्तमान स्थिति ने निश्चित रूप से कामकाजी आबादी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। लेकिन रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों का सिलसिला बढ़ रहा है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने की दिशा में एक एतिहासिक और युगांतरकारी बदलाव साबित हो सकता है। बाजार की उभरती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कौशल की उन्नति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए, सरकारी और निजी क्षेत्र को एक साथ आपूर्ति और इसके विपरीत क्रम को जोड़ा जा सके। प्रस्तुत शोध आलेख में वर्तमान में कोविड के बाद आर्थिक स्थिति एवं रोजगार की चुनौती और भावी कार्य योजना का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

**मुख्य शब्द:** कामकाजी आबादी, रोजगार, वैश्विक महामारी, भावी कार्य योजना

#### प्रस्तावना

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के निस्संदेह कामकाजी आबादी के एक बड़े वर्ग को तनाह कर दिया है। देश में लाखों कामगार रोग की आशंका और रोजगार छूट जाने की वजह से अपन पैतृक स्थानों की ओर लौट गये। महामारी के कारण नौकरी खोना गंभीर वास्तविकता है। वर्तमान स्थिति ने निश्चित रूप से कामकाजी आबादी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। लेकिन रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों का सिलसिला बढ़ रहा है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने की दिशा में एक एतिहासिक और युगांतरकारी बदलाव साबित हो सकता है। बाजार की उभरती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कौशल की उन्नति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए, सरकारी और निजी क्षेत्र को एक साथ आपूर्ति और इसके विपरीत क्रम को जोड़ा जा सके। प्रस्तुत शोध आलेख में वर्तमान में कोविड के बाद आर्थिक स्थिति एवं

रोजगार की चुनौती और भावी कार्य योजना का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में कामगारों के वापस अपने गांव की ओर पलायन ने अनेक राज्यों के लिए अभूतपूर्व चुनौति खड़ी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी की संभावना ने उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दे पाने की उनकी सह राज्यों की तैयारी को आजमाइश में डाल दिया। स्थानीय स्तर पर लाभदायक रोजगार दे पाने की समस्या का समाधान केवल बाजार संचालित अवसरों पर ही निर्भर नहीं है क्योंकि बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं जिनमें अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र अल्प विकसित भी हैं। इस प्रकार की चुनौती को देखते हुए इनमें कई राज्यों की सरकारों ने व्यापक व्यवस्थाओं की घोषणा की।

रोजगार उपायों में वापस आए कामगारों और उनके कौशल स्तरों का पंजीकरण करना तथा केंद्र या राज्य

सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में रोजगार के अवसर से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना शामिल है। हालांकि यह प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है। कि इस तरह के काम को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर ऐसी मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता है जिन्हें गंभीरता से नियोजन और कार्यान्वयन की भारी क्षमता हो। आज देश में कार्यबल का 6.1 प्रतिशत हिस्सा बेरोजगार बताया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भारत ने जो-जो कदम उठाये उनका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों और व्यवसायिक क्षेत्र को सहारा देना था। इसीलिए भोजन उपलब्ध कराने, जन-धन खातों में नकदी अंतरण, छोटे उद्यमों को सरकारी ऋण गारंटी और वित्तीय सहायता सीमाओं में छूट और मोहलत जैसे उपाय किये गये।

अक्टूबर 2020 के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था को तालाबंदी से लगभग पूरी तरह खोल दिया गया है, तो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को

केन्द्र में रखकर कदम उठाने जरूरी है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिसके साथ बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार जुड़े हैं। हालांकि इस पैकेज के बारे में कुछ आशंकाएं थी कि यह भारत को आयात प्रतिस्थापन युग में वापस धकेल सकता है जिसके कारण संतुलन का स्तर कम होगया और विकास घटा लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भी स्पष्ट किया कि इस पैकेज का लक्ष्य भारत को विश्व का विनिर्माण केन्द्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने इस पैकेज के पांच स्तंभों को भी सुझाया है और वे हैं:—अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, तंत्र, जीवंत जनसंख्यिकी यानी लोग और मांग। लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता है 20 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज।

तालिका-1 में नीतिगत उपायों का विवरण दिया गया है जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए गए हैं—

**तालिका 1: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न पहलों का विवरण करोड़ रु० में)**

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना	1,70,000
भारतीय रिज़र्व बैंक तरलता उपाय	8,01,603
आत्म निर्भर पैकेज का भाग-1(एम.एस.एम.ई को संपार्श्विक मुक्त स्वतः एन.बी.एफ.सी./एच.एफ.सी./एफ.आई. के लिए योजनाएं शामिल हैं)	5,94,550
आत्म निर्भर पैकेज का भाग-2(प्रवासियों को मुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति, मुद्रा ऋण के लिए व्याज, स्थान, नर्बाड, के.सी.सी. के लिए योजना शामिल है।)	3,10,000
आत्म निर्भर पैकेज का भाग-3(कृषि अवसंरचना, मत्स्य पालन, पशुपालन, जड़ी बूटियों की खेती आदि)	1,50,000
आत्म निर्भर पैकेज का भाग-4 (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण)	8,100
आत्म निर्भर पैकेज का भाग-5 (मनरेगा)	40,800
अन्य	22,800
कुल	20,97,053

स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका में नीतिगत उपायों का विवरण दिया गया है जोकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए गए हैं। इसमें ऋण गारंटी, सुरक्षा, नौकरियां, गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम आदि पहले शामिल है।

आज देश में नौकरियों के अवसर बढ़ने का रुझान दिखाई दे रहा है। वर्ष 2022 तक मानव संसाधन की जरूरतों का क्षेत्रवार अनुमान निम्न तालिका-2 में दिया गया है। वर्ष 2017 और 2022 के मानव संसाधन की जरूरतों में कुल अंतर 10.34 करोड़ का है। ये आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि आने वाले वर्षों में नौकरी के अवसरों में काफी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। मगर रोजगार के

उभरते परिदृश्य का फायदा उठाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं में कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत है।

आज देश में रोजगार पैदा करना ही पयाप्त नहीं है। इससे गरीबी और असमानता मिटाने में मदद मिलने में मदद मिलनी चाहिए। बड़ी संख्या में रोजगार शुदा लोग भी भयंकर दरिद्रता में जी रहें हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में इस तरह की स्थिति आम बात है। इसलिए चुनौती सिर्फ ज्यादा रोजगार पैदा करने की और इसके लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने की ही नहीं बल्कि रोजगार शुदा लोगों की उत्पादकता बढ़ाने की भी है।

तालिका 2: 2022 तक मानव संसाधनों की जरूरतों का क्षेत्रवार अनुमान

क्र०सं०	क्षेत्र	2017 में मानव संसाधनों की जरूरत(मिलियन मे)	2022 में मानव संसाधनों की जरूरत(मिलियन मे)	में मानव संसाधनों की जरूरत (2022-2017 (मिलियन मे)
1	कृषि	229	215.5	13.5
2	भवन निर्माण और जमीन जायदाद	60.4	91	30.6
3	खुदरा व्यापार	45.3	56	10.7
4	परिचालन तंत्र, परिवहन और भंडार	23	13.2	8.2
5	कपड़ा और वस्त्र	18.3	25	6.7
6	शिक्षा और कौशल विकास	14.8	18.1	3.3
7	हथकरघा और हस्तशिल्प	14.1	18.8	4.7
8	वहन और वाहनों के पुर्जे	12.8	15	2.2
9	निर्माण सामग्री और इमारती हार्डवेयर	9.7	12.4	2.7
10	निजी सुरक्षा सेवाएं	8.9	12	3.1
11	खाद्य प्रसंस्करण	8.8	11.6	2.8
12	पर्यटन आतिथ्य और यात्रा	9.7	14.6	4.9
13	घरेलू सहायक	7.8	11.1	3.3
14	जवाहरात और जेवर	6.1	9.4	3.3
15	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	6.2	9.6	3.4
16	सौंदर्य और सेहत	7.4	15.6	8.2
17	फर्नीचर और फर्निशिंग	6.5	12.2	5.7
18	स्वास्थ्य सेवा	4.6	7.4	2.8
19	चमड़ा और चमड़े के सामान	4.4	7.1	2.7
20	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं	3.8	5.3	1.5
21	बैंकिंग, वित्त सेवाएं और बीमा	3.2	4.4	1.2
22	दूर संचार	2.9	5.7	2.8
23	फार्मास्यूटिकल	2.6	4	1.4
24	मीडिया और मनोरंजन	0.7	1.3	0.6
	कुल	510.8	614.2	103.4

स्रोत: एनवर्नमेंटल स्कैन रिपोर्ट 2016 एन.एस.डी.सी.

कोविड-19 महामारी को देखते हुए रोजगार पैदा करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में रोजगार सृजन की समुचित रणनीति प्रासंगिक और जरूरी है। सरकार ने समावेशी विकास हासिल करने के लिए अनेक पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में तेज सामाजिक-अर्थिक प्रगति और समावेशी विकास के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी योजनाओं की सफलता प्रभावी और जवाबदेही और पारदर्शिता का अनुपालन भी महत्वपूर्ण है।

### निष्कर्ष

कोविड-19 को देखते हुए रोजगार पैदा करना एक बड़ी चुनौती है ऐसे में रोजगार सृजन की समुचित रणनीति प्रासंगिक और जरूरी है यह सच है कि कोविड-19 के कारण भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लेकिन यह समझना होगा कि कोविड-19 की वजह से रोजगारों का नुकसान अस्थायी है कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में कामगारों को उनके पैत्रिक स्थानों से लाना और उन्हें रोजगार के समुचित अवसर मुहैया कराना निस्संदेह एक मुश्किल काम होगा। आज देश में नौकरियों के 90% से ज्यादा अवसर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम

(एम एस एम ई) क्षेत्र मुहैया कराता है। एम.एस.एम.ई क्षेत्र जितनी जल्दी पटरी पर लौटे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति के लिए उतना ही बेहतर होगा। कोविड-19 की आपदा ने कुछ अवसर भी पैदा किए हैं जिनका एमएसएमई क्षेत्र इस संकट से उबरने और फलने-फूलने में इस्तेमाल कर सकता है आज देश में रोजगार पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है इससे गरीबी और असमानता घटाने में मदद भी मिलनी चाहिए। इसलिए चुनौती सिर्फ ज्यादा रोजगार पैदा करने की और इसके लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने की ही नहीं बल्कि रोजगारशुदा लोगों की उत्पादकता बढ़ाने की भी है आज सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समग्र विकास की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं छूटे। भारत सरकार की पहल देश में उद्यमिता, नवाचार और समावेशन में महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रही है। अपेक्षित नतीजे हासिल करने के लिए योजनाओं को बनाने के साथ ही उन्हें निर्धारित समय सीमा और सीमित संसाधनों के बीच सही ढंग से लागू करने की भी जरूरत है। इन सभी योजनाओं की सफलता प्रभावी और कुशल शासन, समयबद्ध क्रियान्वयन और समुचित निगरानी पर निर्भर करती है

### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पाटकर, जुथिका मिश्र, डॉ० मनीष, "रोजगार के लिए संकल्प" नवम्बर 2020 पृष्ठ सं०-24
2. भानुमूर्ति, एन.आर., मोहन मीरा, "अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार" योजना नवम्बर 2020 पृष्ठ सं०-14
3. म्हापात्र ए.के.(2020) माइग्रेंट्स मिजरी एंड लाइवली हुड मैपिंग: द अनफिनिशड एजेंडा, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। 8(4), पृष्ठ सं० 4-71
4. झा. एस. के और कुमा ए (2020) रीवाइटलाइजिंग एम. एस.एम.ई. सेक्टर इन इंडिया: चैलेंजेज एंड द रोड अहेड, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। 8(5) पृष्ठ सं० 4-10
5. म्हापात्र डॉ० अभिय कुमार और झा, डॉ० श्रीरंग के, "समावेशी विकास और रोजगार सृजन", योजना नवम्बर 2020 पृष्ठ सं०-28-29
6. महापात्र ए. के. (2016)। ऑगमेंटिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रुरल इंडिया। कुरुक्षेत्र। 65(2), पृष्ठ सं०-10-14